भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3354

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

.....

उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन

3354. डॉ. राजकुमार सांगवानः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बागपत जिले सहित उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है और इसके प्रारंभ से लेकर अब तक कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा दी गई है;

(ख) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों के बीच जल उपयोग दक्षता में सुधार लाने और सतत सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने कृषि उत्पादकता और किसानों की आय पर प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेतों में पानी की वास्तविक उपलब्धता बढ़ाना, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में जल उपयोग की दक्षता में सुधार करना, सतत जल संरक्षण पद्धतियों को लागू करना आदि था। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) पीएमकेएसवाई के दो प्रमुख घटक हैं, जिन्हें जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश की चार (04) प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं जिनमें सरयू नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना चरण-II और बाणसागर नहर परियोजना को पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के उप-घटक कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी और डब्लूएम) के अंतर्गत सरयू नहर परियोजना और अर्जुन सहायक परियोजना में कमान क्षेत्र विकास सहित पीएमकेएसवाई के एआईबीपी घटक में शामिल किया गया है। वर्ष 2016-25 के दौरान इन

परियोजनाओं के अंतर्गत 768.63 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है और 7.32 हजार हेक्टेयर कमान क्षेत्र विकसित किया गया है। इन परियोजनाओं से लक्षित लाभार्थियों की संख्या 43.22 लाख आंकी गई है। तथापि, इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश के बागपत जिले को कोई लाभ नहीं मिलता है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही पर ड्रोप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) योजना मार्च 2022 तक पीएमकेएसवाई की अम्ब्रैला योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की गई थी और अब प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2015-16 से उत्तर प्रदेश के 556.79 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई विकसित की गई है, जिसमें से 6067 हेक्टेयर क्षेत्र बागपत जिले में आता है। उत्तर प्रदेश में पीडीएमसी योजना से लाभान्वित किसानों की संख्या 3.97 लाख है।

पिछले पांच वर्षों में इन योजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है।

क्र.सं.	**पीएमकेएसवाई के घटक**	**केंद्र सरकार द्वारा दी गई केंद्रीय सहायता (रुपये करोड़ में)**					
		2020-21	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26***
1.	पीएमकेएसवाई-एआईबीपी	391.84	0	23.91	0	0	0
2.	पीएमकेएसवाई-सीएडी और डब्ल्यूएम	6.00	0	0	0	0	0
3.	पीडीएमसी	200.00	150.00	149.25	133.49	173.87	264.21

*दिनांक 09.03.2026 तक

(ग) और (घ): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत सिंचाई दक्षता में सुधार के लिए सिंचाई प्रणालियों का आधुनिकीकरण, भूमिगत पाइपलाइनें, सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली) और सटीक सिंचाई प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को फसल विविधीकरण, जल-बचत कृषि पद्धतियों और जल उपयोगकर्ता संघों के माध्यम से सहभागी सिंचाई प्रबंधन को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (एमसीएडी) के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से एक पायलट योजना शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य स्थापित स्रोत से लेकर फॉर्म गेट तक भूमिगत दबावयुक्त पाइप सिंचाई के माध्यम से किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई के लिए मजबूत आधारभूत संरचना के साथ सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है। इससे जल उपयोग दक्षता और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।

वर्ष 2016-25 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत 29.23 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। इससे खेतों तक जल की पहुंच बढ़ी है। इस अवधि के दौरान 22.21 लाख हेक्टेयर में कमान क्षेत्र विकास और पीडीएमसी के अंतर्गत 11 मिलियन हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई विकास के साथ कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

*****